भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3974
25 **मार्च**, 2025 **को उत्तर के लिए**

आदर्श ग्राम मात्स्यिकी परियोजनाएं

3974. **श्री इटेला राजेंदर**:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई आदर्श ग्राम मात्स्यिकी परियोजनाओं को शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है एवं इसके लिए स्वीकृत और व्यय की गई निधि तथा पुरानी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बिहार और ओडिशा द्वारा इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या अन्तर्देशीय जल संसाधनों में वृद्धि करने और तेलंगाना राज्य में लगभग 274 किमी लम्बाई को शामिल करते हुए गोदावरी नदी तल के एक बड़े खण्ड को मत्स्य गलियारे में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है ताकि रोजगार की व्यापक संभावना का पता लगाया जा सके और प्रति वर्ष 10000 करोड़ रुपये की अनुमानित मत्स्य संपदा का सृजन किया जा सके?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) अन्य बातों के साथ-साथ इंटीग्रेटिड मॉडर्न कोस्टल फिशिंग विलेज के विकास के लिए तटीय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक इंटीग्रेटिड कोस्टल फिशिंग विल्लेज के विकास के लिए परिकल्पित इकाई लागत केंद्र और संबंधित तटीय राज्य सरकार के बीच 60:40 के आधार पर साझा की जाती है और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में भारत सरकार 100% इकाई लागत को वहन करती है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, 11 इंटीग्रेटिड मॉडर्न कोस्टल विल्लेज के विकास के लिए 7756.46 लाख रुपए के कुल निवेश के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें (i) केरल में 6106.61 लाख रुपए की लागत से नौ कोस्टल विल्लेज, (ii) लक्षद्वीप में 899.85 लाख रुपए की लागत से एक कोस्टल विल्लेज और (iii) पश्चिम बंगाल में 750 लाख रुपए की लागत से एक कोस्टल विलेज शामिल हैं। इसके अलावा, पीएमएमएसवाई के अंतर्गत, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से पीएमएमएसवाई के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए के कुल निवेश से तटरेखा के करीब स्थित कुल 100 कोस्टल फिशरमन विल्लेजस को क्लाइमेट रेसीलिएन्ट कोस्टल फिशरमन विल्लेजस (सीआरसीएफवी) के रूप में विकसित करने हेतु पहचान की है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ फिशरमन विल्लेज बनाया जा सके। चूंकि पीएमएमएसवाई के अंतर्गत ये गतिविधियां तटवर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही हैं, अत: उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में मॉडल फिशरीज़ विलेज के विकास के लिए कोई परियोजना नहीं शुरू की गई है।

(ख): तेलंगाना सरकार ने सूचित किया है कि तेलंगाना एक अंतर्देशीय राज्य है, जहां बड़ी संख्या में छोटे, मध्यम और बड़े जल निकाय हैं, अत: राज्य सरकार का ध्यान अंतर्देशीय मात्स्यिकी के विकास पर रहा है और राज्य सरकार द्वारा नदी में मात्स्यिकी (रिवरीन फिशरीस) की संभावनाओं को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है।

*****